भारतीय सीमेंट निगम को हो रहे घाटे

1891. **श्री सुनील बसु राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम को घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और घाटा होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) घाटा कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान सी. सी० आई० द्वारा उठाया गया घाटा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये में)	
1985-86	12.36	
1986-87	21.02	
1987-88	47.00	(अनन्तिम)

हानि के मुख्य कारण ये हैं--अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाना, चूना पत्थर पर कर व रायल्टी में वृद्धि, बार-बार की लोड शेडिंग से उत्पादन में कमी होना आदि।

(ग) सी० सी० आई० ने कम्पनी द्वारा उठाए जा रहे घाटे को कम करने के लिए कई कदम उठाए है। इनमे उन क्षेत्रों का पता लगाकर जहां प्रमुख अन्तर्वस्तुओं जैसे बिजली और कोयले की खपत में कमी संभव हो, उत्पादकता में सुधार करना, डी० जी० सैटो की अधिष्ठापन प्रि-केलसिनेटर/अनुषंगी अग्नि प्रणालियों की अधिष्ठापना के रख-रखाव के उपायों में वृद्धि तथा संयंत्रों के आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं।

Forest-based and mineral-based industries in Orissa

1892. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is a great scope for setting up forest-based and mineral-based Industry in Keonjher, Mayurbhanj and Sundargarh districts of Orissa; and

(b) if so, the steps taken so far in the seventh Five Year Plan period to set up such industry in these districts of Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) There is scope for setting up industries in these districts based on available forest and mineral resources.

(b) An outlay of Rs. 120 Crores has been made in seventh Five Year Plan of Orissa State for Large and Medium, Village and small scale industries. It is for the State Government to formulate scheme for industrialisation of various districts including these three districts within the approved outlay.

Keonjher, Mayurbhanj and Sundergarh districts of Orissa are covered under centrally sponsored programme of District Industry Centres. These DICs have prepared detailed action plans of the respective districts identifying scope for establishment of new industries in the district; based on skill, demand and resources available in the district. In addition, several Letters of Intent and Industrial Licences have been issued for setting up industries in these districts. A mini paper plant based on sabai grass has also been set up in Jharia in Mayurbhanj district.

Steps to increase the production of newsprint

1893. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a severe scarcity of newsprints in the country;

(b) if so, what steps have been taken to increase its production;

(c) whether it is also a fact that steps have been taken to increase the import of newsprint; and

(d) if so, what is the total quantum of newsprint proposed to be imported in 1988-89?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Newsprint is imported only to make good the shortfall in the availability of indigenous newsprint. Newsprint upto a maximum of Rs. 200 crores is proposed to be imported during 1988-89?

Collaboration between General Foods Corporation Limited, U.S.A. and M|s. Kothari General Foods Corporation Limited

1894. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Starred Question 336 given in the Rajya Sabha on 30th November, 1987 and state:

(a) the date on which the deed of assignment was executed between M|s. General Foods Corporation of USA and M|s. Kothari General Foods Corporation Limited and whether it has been accepted by Government; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The deed of Assignment was executed between M|s. General Foods Corporation, New York 10801 and M|s. Kothari General Foods Limited, Madras on 3rd June, 1987. M|s. Kothari General Foods Corporation Ltd., Madras, filed a request with the Registrar of Trade Marks, Bombay, to bring their name on record claiming to be the Proprietors of the Trade Mark "Tang" on the strength of the deed of assignment. The proceedings are pending before the Registrar of Trade Marks.

दिल्ली के पूर्वी-भाग में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की "सैल्फ सप्लाई" की सुविधा

1895. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विशेषतया पूर्वी दिल्ली में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के डीलर ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके गैस के सिलेण्डर 15 से 20 दिन में समाप्त हो जाते हैं, सिलेण्डरों की "सैल्फ सप्लाई" की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं और उन्हें, क्योंकि उनके राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की संख्या 6 से अधिक होती है, "सैल्फ सप्लाई" के स्थान पर घर पर दी जाने वाली सिलैन्डर सप्लाई की सुविधा को स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार इस बात को रोकने और उपभोक्ताओं को "सैल्फ सप्लाई" की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में तेल कम्पनियों ने एल.पी.जी. की सप्लाई के बारे में पैसा दो और माल उठाओ की प्रणाली को बंद कर दिया है। एल.पी.जी. को अप्रतिबंधित उपभोक्ताओं के